राज्य योजना आयोग (नियोजन विभाग), उत्तराखण्ड

आउटकम बजट 2018–19

(धनराशि लाख रू0 में)

योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले		परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट	समय सीमा	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम	समय सीमा
		राजस्व	पूंजीगत				
अनुदान संख्या–07 राज्य सेक्टर 3451–सचिवालय आर्थिक सेवायें 092–अन्य कार्यालय 03–नियोजन अधिष्ठान	राज्य की नीति एवं नियोजन की प्रक्रिया हेतु	1200.01		राज्य योजना आयोग में 101 कार्मिकों के अधिष्ठान के व्यय हेतु	01 वर्ष	नियोजन प्रक्रिया के अन्तर्गत राज्य पर विभिन्न प्रकार के मूल्यांकन एवं विकास कार्यों में आवश्यक परामर्श प्रदान करना।	01
04–आयोजनागत विकास कार्यों का मूल्यांकन 16–व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	प्रदेश में कराये गये अवस्थापना निर्माण कार्य की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु एवं भविष्य में सुधार के लिए तकनीकी जांच/मूल्यांकन कार्य विशेषज्ञ संस्थाओं से नियमित रूप से सम्पादित कराये जा रहे है।	500.00		नव सृजित राज्य की आर्थिक स्थिति, संसाधनों, जनआकाक्षाओं एवं अपेक्षाओं के अपेक्षानुसार कार्यक्रमों का गहन परीक्षण, मूल्यांकन, स्थलीय सत्यापन व व्यापक सर्वेक्षण एवं लक्ष्य प्राप्त करना।	01 वर्ष	अवस्थापना निमार्ण कार्यों की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु।	01
07 परियोजना विकास निधि का गठन 20–सहायक अनुदान अंशदान/राज सहायता	राज्य में पी0पी0पी0 के अन्तर्गत परियोजनाओं का सम्यक् विकास एवं सुचारू क्रियान्वयन हेतु राज्य में PPP enabling framework सृजित किये जाने हेतु।	50.00		अधिक से अधिक विभागों की सटीक परियोजना प्रतिवदनों एवं व्यहार्यता रिपोर्ट की संरचना।	01 वर्ष	ससमय परियोजनाओं का प्रारम्भ निर्बाध क्रियान्वयन एवं चरणबद्ध रूप में पूर्ण किया जाना।	01
99–पी0पी0पी0 प्रकोष्ठ का गठन 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	उत्तराखण्ड अवस्थापना व्यवहार्यता (Viability) अनुदान योजना के अन्तर्गत राज्य में सार्वजानिक निदेश के पूरक के तौर पर आवश्यक निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए व्यवहार्य (Viable) परियोजनाओं के चिन्हन, प्रोजेक्त निरूपण, फिजिविलिटी रिपोर्ट का परीक्षण।	128.00		अधिक से अधिक संख्या में विभागों को पी.पी.पी. परियोजनाओं के Concept Note तैयार करने, RFP डाक्यूमेण्ट तैयार करने निविदा प्रक्रिया सम्पन्न करने में सहयोग।	01 वर्ष	पी.पी.पी. मोड में अधिक से अधिक निजी निवेश प्राप्त करना तथा गुणवत्तायुक्त Service Delivery का लक्ष्य प्राप्त करना।	01
99–उत्तराखण्ड स्टेट सेन्टर फार पब्लिक पालिसी एण्ड गुड गवर्नेस (सी0पी0पी0जी0जी0) का गठन 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	राज्य के सतत विकास हेतु नियोजन एवं नीति नियोजन को प्रभावी, उपयोगी तथा अकादमिक संस्थाओं एवं विषय विशेषज्ञों के सहयोग से क्रियात्मक शोध एवं नीति प्रपत्र तैयार किया जाना।	100.00		नियोजित विकास हेतु नीतियों का निर्माण	01 वर्ष	समय–समय पर नीतियों का क्रियान्वयन हेतु कार्यवृद्धिया	01